

वेबपोर्टल ई-सनद शुरू : सत्यापन के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

विदेश जाने वाले छात्रों को मिलेंगे ऑनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र

डेली न्यूज

नई दिल्ली > 24 मई

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को उनकी अंकसूचियों एवं अन्य प्रमाणपत्रों का विदेश मंत्रालय से सत्यापन कराने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए बुधवार को यहां एक वेबपोर्टल ई-सनद शुरू किया गया।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां जवाहरलाल नेहरू भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल के तहत इस पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। इस मौके पर स्वराज ने कहा कि इस पहल के माध्यम से विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले हजारों छात्रों को तमाम समस्याओं और भारी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकेगी। उन्हें जानकारी है कि इस काम के लिए एक बड़ा रैकेट काम करता था और देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों से उनके दस्तावेजों के विदेश मंत्रालय से सत्यापन के नाम पर हजारों लाखों रुपए ऐंठता था। स्वराज ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परिणाम मंजूषा और तेलंगाना सरकार के परिणाम पोर्टल से जोड़ा गया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट



भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मंत्रिमंडलीय बैठक में कहा था कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों में तकनीक खासकर डिजिटलीकरण के माध्यम से सेवाओं का सरलीकरण करें, पारदर्शी बनाएं और भ्रष्टाचार को समाप्त करें। उनका मानना है कि जटिल प्रक्रियाओं के कारण कुछ लोगों को असुविधा होती और बहुतों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। मोदी ने तकनीकी सुधारों को युवानुकूल बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने पासपोर्ट संबंधी नियमों को सरल बनाया है, जिससे पासपोर्ट आवेदनों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से प्रवासी कामगारों के लिए ई-माइग्रेट और प्रवासी भारतीयों के लिये ई-मदद पोर्टल भी लोगों के लिए भारी राहत लेकर आए हैं।

मामूली शुल्क पर सत्यापन

बच्चे इस पोर्टल के माध्यम से मामूली शुल्क ऑनलाइन देकर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ई-सनद को अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। जल्द ही सभी 48 माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, राज्यों एवं केंद्र के विश्वविद्यालयों, केंद्रीय संस्थानों के निर्माणाधीन एकीकृत डिजिटल राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कोश से भी जोड़ दिया जाएगा।

तकनीक से मिलेगी राहत

विदेश मंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन के आरंभ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उनसे कहा था कि मंत्री पद सत्ता के लिए सेवा के लिए लेना और सत्ता को व्यवस्था परिवर्तन के उपयोग में लाना। वह यही करने का प्रयास कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूर के विभाग को दिल के करीब लाने में तकनीक का प्रयोग ही डिजिटल इंडिया मूलतः यही है। तकनीक को सरल सुलभ सस्ती समग्र और विकासात्मक होनी चाहिए। उन्होंने ई-अस्पताल, डिजिटल लाभ हस्तांतरण, ई-वीसा आदि के उदाहरण देते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।

48 बोर्ड और 100 केंद्रीय संस्थान जुड़ेंगे

जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से छात्रों को अब अलग-अलग स्थानों के लिये दौड़धूप नहीं करनी होगी। जल्द ही 48 बोर्ड और 100 केंद्रीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़ जायेंगे। सीबीएसई के प्रमुख आर के चतुर्वेदी ने बताया कि 2014 से 2017 तक के दसवीं एवं बारहवीं के करीब 37 लाख छात्रों की अंकसूची, प्रमाणपत्र एवं माईग्रेशन परिणाम मंजूषा में डिजिटल लॉकरों में उपलब्ध कराया गया है।